पंजाब केसरी

Tue, 24 Dec 2019

भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया

मिसाइल का सफल परीक्षण किया

बालासोर (ओडिशा), (भाषा) भारत ने सोमवार को ओडिशा तट के पास एक परीक्षण स्थल से सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल (क्यूआरएसएएम) प्रणाली का सफल परीक्षण किया जिसके 2021 तक सशस्त्र बलों के आयुध भंडार में शामिल होने की संभावना है।रक्षा विभाग के एक बयान में कहा कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित इस मिसाइल का परीक्षण पूर्वाह्न 11:45 बजे चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र (आईटीआर) से किया गया।

बयान में कहा गया कि परीक्षण में क्यूआरएसएएम ने लक्ष्य को हवा में ही मार गिराया और मिशन उद्देश्य पूरे कर लिए गए।इसमें कहा गया कि मिसाइल के दागे जाने और लक्ष्य को निशाना बनाने जैसी पूरी प्रक्रिया पर ग्राउंड टेलीमेट्री सिस्टम, रेंज रडार सिस्टम और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम द्वारा नजर रखी गई। परीक्षण के दौरान महानिदेशक (मिसाइल एवं रणनीतिक प्रणाली), एमएसआर प्रसाद मौजूद थे।बयान में कहा गया कि इस

मिशन के साथ ही संबंधित अस्त्र प्रणाली के विकासात्मक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे हो गए हैं। और इसके 2021 तक सशस्त्र बलों के आयुध भंडार में शामिल होने के लिए तैयार हो जाने की उम्मीद है।

THE TIMES OF INDIA

Tue, 24 Dec 2019

India successfully test-fires quick reaction surface-to-air missile system

By Rajat Pandit

New Delhi: The indigenous quick-reaction surface-to-air missile (QRSAM) system - which is designed to intercept hostile fighters, helicopters and drones at a range of up to 30km - was successfully tested from the Chandipur integrated test range off the Odisha coast on Monday.

The QR-SAM, with the latest test completing its developmental trials, is "expected to be ready" for induction by 2021, said Defence Research and Development Organization (DRDO) officials. The QR-SAM project was sanctioned in August 2014 at an initial development cost of Rs 476 crore, with the first test being conducted in June 2017. The armed forces have inducted some Israeli Spyder QR-SAM units in the absence of such indigenous systems.

In the test on Monday, the single-stage missile was flight-tested with "full configuration in deployment mode" and successfully intercepted the target un mid-air to meet the mission objectives. The QR-SAM system, which operates on the move, includes a fully-automated command and control system, an active array battery surveillance Radar, an active array battery multi-function radar and the launcher.

"Both radars are four-walled having 360-degree coverage with search on move and track on move capability. The system is compact with minimum number of vehicles for a firing unit. The solid-propellant missile has mid-course inertial navigation system with two-way data link and terminal active seeker developed indigenously by DRDO," said an official.

The QR-SAMs, which are stored in canisters and mounted on trucks, are also equipped with electronic counter-measures to prevent jamming by hostile aircraft. "The entire test on Monday was monitored by ground telemetry systems, range radar systems and electro-optical tracking systems, " he added.

https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-successfully-test-fires-quick-reaction-surface-to-air-missile-system/articleshow/72941111.cms

THE ECONOMIC TIMES
WWW.ECONOMICTIMES.COM

Tue, 24 Dec 2019

DRDO's quick-reaction missile test successful

"The missile (Quick Reaction Surface to Air Missile) was flight-tested with full configuration in deployment mode intercepting the target mid-air, meeting the mission objectives. The entire event was monitored by Ground Telemetry Systems, Range Ra..

New Delhi: The Defence Research and Development Organisation (DRDO) successfully flight-tested indigenously developed Quick Reaction Surface to Air Missile (QRSAM) system from Chandipur off the Odisha coast on Monday.

"The missile was flight-tested with full configuration in deployment mode intercepting the target mid-air, meeting the mission objectives. The entire event was monitored by Ground Telemetry Systems, Range Radar Systems and Electro Optical Tracking System," said DRDO in a statement.

The weapon system, which operates on the move, comprises fully automated command and control system, active array battery surveillance radar, active array battery multifunction radar and launcher.

Both radars are four-walled having 360-degree coverage with search-on-move and trackon-move capability.

The system is compact with a minimum number of vehicles for a firing unit. The single stage solid propelled missile has midcourse inertial navigation system with two-way data link and terminal active seeker developed indigenously by DRDO.

"The missile successfully engaged the aerial target, establishing its capability," DRDO said. Director General (Missiles and Strategic Systems)M.S.R. Prasad was present during the trial.

The developmental trials of the weapon system are successfully completed and the weapon system is expected to be ready for induction by 2021.

https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/drdos-quick-reaction-missile-test-successful/articleshow/72939402.cms

दैनिक जागरण

Tue, 24 Dec 2019

ब्रह्मोस की ताकत पर दुनिया की मुहर

जयप्रकाश रंजन • नई दिल्ली

भारत और रूस के सहयोग से निर्मित दुनिया की सबसे तेज सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को खरीदने की चाहत रखने वाले देशों की एक तरह से लाइन लग गई है। बहुत संभव है कि पहली बार इस मिसाइल को किस देश को बेचा जा रहा है, इसकी घोषणा अगले वर्ष कर दी जाए। वर्ष 2020 भारत और रूस के रणनीतिक रिश्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है, जब दोनों देशों की तरफ से रक्षा सहयोग से जुड़ी कुछ बड़ी परियोजनाओं का एलान किया जाएगा। ऐसे में दोनों देश ब्रह्मोस मिसाइलों के लिए किसी खरीदार देश का चयन कर वैश्विक स्तर पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे।

नई दिल्ली में रूस के दूतावास के उप प्रमुख रोमन बाहुशकिन ने यह जानकारी दी कि ब्रह्मोस मिसाइस सिस्टम को लेकर दुनिया के तमाम देशों में कितनी उत्सुकता है। फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया समेत तकरीबन 12 देश इसे खरीदने की इच्छा जता चुके हैं। लेकिन, अभी तक किसी देश के साथ बातचीत को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। ब्रह्मोस ने भारत व रूस के रणनीतिक रिश्तों को जो गहराई दी है, उसे अगले वर्ष और पुख्ता किया जाएगा। दोनों देश मिलकर ब्रह्मोस जैसी दूसरी युद्ध प्रणाली भी विकसित कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत कई रक्षा उपकरणों को विकसित करने पर बात हो रही है। रूस चाहता है कि भारत के साथ विकसित होने वाले रक्षा उपकरणों की मार्केटिंग तीसरे देशों में भी की जाए। भारत और रूस अगर ब्रह्मोस को किसी तीसरे देश को बेचने में सफल हो जाते हैं तो यह हथियारों के अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक बड़ी धमक होगी। साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि फिलीपींस जैसे पड़ोसी देशों में मिसाइल सिस्टम बेचने पर चीन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया दिखाई जाती है।

ऐसी है ब्रह्मोस मिसाइल

ब्रह्मोस मिसाइल ऐसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे पनडुब्बी, जलपोत, वायुयान या जमीन से प्रक्षेपित किया जा सकता है। भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम से तैयार इस प्रक्षेपास्त्र को दोनों देशों की ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदी के नामों के शुरुआती अक्षरों को जोड़कर रखा गया है।

वजन	3,000 किग्रा
लंबाई	8.4 मीटर
व्यास	0.6 मीटर
मुखास्त्र	300 किग्रा
क्षमता	290 किमी
रफ्तार	2.8-3.0 मैक

खूबी

- जमीन पर 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लक्ष्य को सटीकता से भेदने में कुशल। इससे सीमापार के क्षेत्रों में बिना तबाही मचाए आतंकी कैंपों को समाप्त किया जा सकता है
- पहाड़ी और ऊबड़-खाबड़ सतहों पर भी इसका प्रभावी उपयोग किया जा सकता है

सबसे तेज : इस मिसाइल की 2.8-3.0 मैक की रफ्तार अमेरिका की हार्पून सबसोनिक मिसाइल की रफ्तार से साढ़े तीन गुना अधिक है

हाइपरसोनिक : ब्रह्मोस परियोजना के तहत हाइपरसोनिक संस्करण भी तैयार किया जा रहा है, जिसकी चाल 5-7 मैक होगी। ब्रह्मोस-द्वितीय नामक यह मिसाइल तब अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल बन जाएगी

दैनिक जागरण

Tue, 24 Dec 2019

ब्रह्मोस खरीदने में दक्षिण एशियाई देश दिखा रहे ज्यादा रुचि

जयप्रकाश रंजन • नई दिल्ली

दुनिया की सबसे तेज सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को खरीदने में अभी तक जितने देशों ने रुचि दिखाई है, उनमें से ज्यादातर दक्षिण एशियाई देश हैं। भारत और रूस साथ मिलकर तीसरे देशों में आणविक ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए भी करार कर चुके हैं, जिस पर चीन की तरफ से पहले ही प्रतिक्रिया जताई जा चुकी है। भारत व रूस बांग्लादेश में एक आणविक ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए वहां की सरकार से बात कर रहे हैं।

रूस के राजदूत निकोलाय कुदाशेव ने बताया कि अगले वर्ष भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच होने वाली मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के आसार हैं। यह व्यापार समझौता भारत और केंद्रीय व उत्तरी यूरेशिया क्षेत्र के देशों (अर्मेनिया, बेलारूस, कजाखस्तान, किर्गिस्तान व रूस) के बीच होगा। भारत की योजना आगे चलकर इसमें अफगानिस्तान, ईरान जैसे दूसरे देशों को भी शामिल करने की है। इस समझौते को और ज्यादा कारगर बनाने के लिए रूस और भारत के बीच होने वाली स्ट्रेटिजिक इकोनॉमिक डायलॉग का और विस्तार किया जा रहा है। यह भी कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा द्विपक्षीय कारोबार दोनों देशों की मुद्राओं में हो सके। अभी भारत व रूस के द्विपक्षीय कारोबार में 30 फीसद लेन देन स्थानीय मुद्रा यानी रूपये और रूबल में होता है। इसे और बढ़ाने के लिए बात हो रही है।

THE ASIAN AGE

Tue, 24 Dec 2019

‘Dozens of countries keen to buy BrahMos’

Babushkin also said Russia has independent strategic ties with both India and China and that the two relationships are independent of each other

By Sridhar Kumaraswami

New Delhi: Top Russian diplomats on Monday said “dozens of countries”, including the Philippines have expressed interest in acquiring the BrahMos supersonic cruise missile — developed jointly by both India and Russia — but that there are several “considerations” involved before granting permission for the sale including “political and economic” factors.

In response to a question about reported interest by the Philippines to acquire the290 km-range missile at an interaction with reporters at the Russian Embassy, Russian Deputy Chief of Mission (DCM) Roman Babushkin said, “Not only Philippines but dozens of countries are interested”.

He added that there are many factors like “political, economic and technical” to be taken into account first before the green signal for sale is given and that “no decision has been taken” on sale to any third country.

Mr Babushkin also said Russia has independent strategic ties with both India and China and that the two relationships are independent of each other. But the Russian Deputy Chief of Mission (DCM) Babushkin clarified, “There is no military alliance with China. We (Russia) don't plan to create one.”

https://www.asianage.com/india/all-india/241219/dozens-of-countries-keen-to-buy-brahmos.html

Business Standard

Tue, 24 Dec 2019

Revamp DRDO, plan on reducing dependance on foreign vendors: Par panel

The panel also recommended that an environment might be created where the public sector and the private sector could work in collaboration

New Delhi: The Parliamentary Standing Committee on Defence has recommended a "complete revamp" of the Defence Research Development Organisation (DRDO) by involving the private sector and academic institutions for its resurgence and chalking out of a plan to reduce dependance on foreign vendors for military hardware.

The recommendations were made by the standing committee, headed by former Union minister and BJP MP Jual Oram, in its report on 'Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2019-20'.

The report has already been submitted to the Lok Sabha speaker and was also tabled in the Rajya Sabha during the winter session of Parliament.

Recommendations and observations of the committee were released by the Lok Sabha Secretariat on Monday.

"The Committee stressed on the need for a complete revamp and re-orientation of DRDO functions and one of the major initiatives suggested by the committee in this regard was to facilitate the active involvement of the private sector, universities, IITs and the Indian Institute of Science, which could play a major role in the resurgence of DRDO," the secretariat said in the statement.

The panel also recommended that an environment might be created where the public sector and the private sector could work in collaboration so that the research and development activities could be synergised and better coordination achieved.

Noting that dependence on the foreign vendors for military hardware has been rising all these years, the panel said the Defence Ministry should "chalk out a plan in consultation with the services, Indian industry, Defence Public Sector Undertakings (DPSUs), educational institutes and other stakeholders to reduce this dependance."

The rising reliance on foreign vendors for hardware required by defence forces has led to very little procurement from the Indian sources, it said.

"This led to very little procurement from the Indian sources as it is inversely proportional to procurement from foreign vendors and would affect our indigenous industry in long run," the panel said.

The committee also felt that a level playing field needs to be provided to the Indian private industry and they might be allowed to tie up with foreign manufacturers to develop certain equipment based on the requirements of users.

(Only the headline and picture of this report may have been reworked by the Business Standard staff; the rest of the content is auto-generated from a syndicated feed.)

https://www.business-standard.com/article/pti-stories/revamp-drdo-by-involving-pvt-sector-make-plans-to-reduce-dependance-on-foreign-vendors-par-panel-119122301259_1.html